छत्तीसगढ़ का पहला मिड-डे अखबार
शहर की
जनता से रिश्ता

एस्सल समूह में निवेश पर एचडीएफसी, कोटक म्यूचुअल फंड को कारण बताओ नोटिस : नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एस्सल समूह की कंपनियों के की रिण प्रतिभूतियों में किये गये निवेश को लेकर एचडीएफसी और कोटक महिन्द्रा म्यूचुअल फंड घरानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एस्सल समूह की कंपनियों में किया गया निवेश फंसने से कई म्यूचुअल फंड कंपनियां को अपनी निवेश योजनाओं की परिपक्वता का भुगतान करने में के दबाव महसूस हो रहा है। एचडीएफसी एएमसी और कोटक महिन्द्रा एएमसी ने अप्रैल में अपनी सावधि जमा योजनाओं के परिपक्वता भुगतान के लिये कुछ और समय की मांग की थी।

सराफा बाजार भाव

रायपुर		
सोना	₹ 32,771	10 ग्राम
चांदी	₹ 40,400	किलोग्राम
मुंबई		
सोना	₹ 32,803	10 ग्राम
चांदी	₹ 37,521	किलोग्राम
लंदन		
सोना	₹ 30,050	10 ग्राम
चांदी	₹ 38,220	किलोग्राम

एनएसई निफ्टी

बीएसई सेंसेक्स

अमेरिका का बड़ा एक्शन, चीन-PAK समेत 12 कंपनियों को निगरानी सूची में डाला

नई दिल्ली (ए.)। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया तो फिर चीन ने भी एक्शन लिया। लेकिन अब अमेरिका ने एक बार फिर पलटवार किया है। सोमवार को अमेरिका ने देश में कुल 12 विदेशी कंपनियों को निगरानी लिस्ट में डाल दिया है, ताकि ये कोई गलत फायदा ना उठा सकें। इन 12 कंपनियों में चीन और पाकिस्तान की कंपनियां भी शामिल हैं।

अमेरिका ने ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र उठाया है, जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल है। जिन 12 कंपनियों को निगरानी सूची में डाला गया है उसमें 4 हॉन्गकॉन्ग-चीन, 2 चीनी, एक पाकिस्तानी और 5 एमरात की कंपनियां हैं।अमेरिकी कॉमर्स मंत्रालय के सेक्रेटरी विल्बर रॉस के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने ये फैसला अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। इस निगरानी लिस्ट में हमने ना सिर्फ कंपनियों को बल्कि चयनित व्यक्तियों को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दे सकते हैं, जहां चीन की कंपनियां अमेरिकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें और यहां की सुरक्षा के लिए खतरा बनें। जिन चार हॉन्गकॉन्ग-चीनी कंपनियों पर बैन लगाया गया है, उनपर ईरान का समर्थन करने का आरोप लगा है। तो वहीं, अन्य कंपनियों/व्यक्तियों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। जबकि जिस पाकिस्तानी कंपनी को निगरानी सूची में डाला गया है उसपर न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। यही कारण है कि अब उसपर अमेरिका की नज़र रहेगी। बता दें, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार मसले को लेकर 11वें दौर की बातचीत असफल होने के बाद अब दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई है। समस्या का हल नहीं निकलने के लिए अमेरिका ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने व्यापार वार्ता के विफल होने का दोष चीन पर मढ़ दिया है। तभी से ही दोनों देशों में वार-पलटवार का सिलसिला जारी है।

चीन ने अमेरिका के 60 अरब डॉलर के सामानों पर बढ़ाया टैरिफ

बीजिंग (ए.)। चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर जवाबी कदम उठाते हुए 60 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों पर सोमवार को आयात-शुल्क बढ़ा दिया। इससे पहले अमेरिका ने चीन के 200 अरब डॉलर के सामानों पर शुल्क बढ़ाया था। चीन सरकार ने कहा है कि वह ' 'विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को चेतावनी दी कि यदि चीन ने उसके साथ व्यापार समझौता नहीं किया तो ' 'वह बुरी तरह से प्रभावित होगा। उसके कुछ ही घंटे बाद चीन के वित्त मंत्रालय ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि अमेरिका के आने वाले 60 अरब डॉलर के विभिन्न प्रकार के माल पर प्रशुल्क बढ़ाकर क्रमश: 25, 20 और 10 प्रतिशत किया जाएगा।

व्यापार समझौता नहीं करने से बुरी तरह प्रभावित होगा चीन: ट्रंप : चीन ने इसे अमेरिका की एकतरफा प्रशुल्कीय कार्रवाई के जवाब में उठाया गया कदम बताया है। मंत्रालय ने बयान में कहा, ' 'चीन को उम्मीद है कि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की सही पटरी पर लौटेगा, चीन के साथ काम करेगा और आपसी सम्मान एवं बराबरी पर आधारित दोनों पक्षों के लिये फायदेमंद समझौता करेगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल अप्रैल में व्यापार युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों ने गतिरोध समाप्त करने के लिये बातचीत की शुरुआत की थी। हालांकि 11वें दौर की बातचीत के बेनतीजा समाप्त होने के बाद अमेरिका ने चीन के 200 अरब डॉलर के सामानों पर शुक्रवार से अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल चीन ने अमेरिका को 539.50 अरब डॉलर का निर्यात किया।

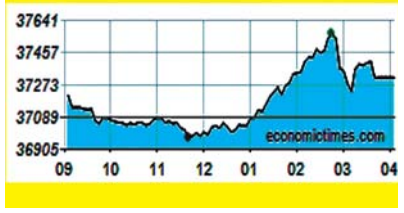

खाद्य पदार्थों के दाम में वृद्धि मुख्य वजह

खुदरा महंगाई दर : आने वाली सरकार के लिए चिंता का विषय

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र में आने वाली सरकार के सामने महंगाई पहले से ही चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर अप्रैल महीने में बढ़कर 2.92 प्रतिशत हो गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इससे पिछले महीने 2.86 फीसदी और एक साल पहले अप्रैल 2018 में 4.58 फीसदी पर थी। आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की श्रेणी में महंगाई दर अप्रैल में 1.1 फीसदी पर पहुंच गई जो मार्च में 0.3 फीसदी थी। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर गौर करता है।

आने वाली सरकार के सामने चुनौती : दरअसल पिछले कुछ महीनों में कई खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में सूखे और गर्मी जल्दी आने की वजह से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं। महंगाई दर में बढ़ोतरी केंद्र में आने वाली सरकार के लिए चिंता विषय है। गौरतलब है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौर में देश को महंगाई से काफी राहत मिली थी। खाद्य महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों काफी नीचे रहे। लेकिन अब केंद्र में जो भी सरकार आएगी, उसके लिए बढ़ती महंगाई फिर से एक चुनौती पैदा कर सकती है। हालांकि इसके बावजूद यह रिजर्व बैंक के लिए सुविधाजनक स्तर 4 फीसदी से कम है।

महंगाई बढ़ने से लोग परेशान : यूपीए सरकार के दौर में महंगाई के काफी ऊंचे आंकड़ों की वजह से ही जनता परेशान हो गई थी और इसकी वजह से सरकार के खिलाफ माहौल बन गया था। लेकिन इस बार के आम चुनाव में महंगाई कोई मसला ही नहीं है।बता दें, लगातार 9 महीने से महंगाई रिजर्व बैंक के लिए सुविधाजनक स्तर पर बनी हुई है। रिजर्व बैंक फरवरी और अप्रैल महीने में दो बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है। जबकि मार्च में महंगाई दर 2.86 फीसदी थी। सब्जियों, अनाज जैसी खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ने की वजह से मुख्य महंगाई का आंकड़ा बढ़ रहा है।

आगे भी महंगाई दर बढ़ने की आशंका : यही नहीं, आने वाले महीनों में महंगाई दर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार चुनावों को देखते हुए देश में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, यानी चुनावों के बाद इनकी कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। ईंधन की कीमतों के बढ़ने खाद्य वस्तुओं की कीमतें और बढ़ जाएंगी।

नोटबंदी: ED की बड़ी कार्रवाई

Axis बैंक मनी लांड्रिंग मामले में 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

मुंबई (ए.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लांड्रिंग मामले में 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला 2016 में नोटबंदी के बाद यहां एक्सिस बैंक शाखा के पूर्व अधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ दायर प्रकरण से जुड़ा है।

एक बयान में ईडी ने कहा कि उसने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया। इसके तहत एक्सिस बैंक नोटबंदी मुद्रा अदला-बदली मामले में पुनीत जैन, हेमराज सिंह, विनोद देशमुख, राजीव सिंह कुशवाहा, महफूज खान, परवेश कुमार गांधी और अन्य की 2,95,92,351 रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की गयी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया था। वर्ष 2016 में 1,000 रुपये के कुल 3.70 करोड़ रुपये मूल्य के नोट बरामद होने के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की थी।

बयान के अनुसार जांच से पता चला है कि नोटबंदी की घोषणा के बाद आरोपी मोहित गर्ग, नितिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, शोभित सिन्हा और एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने विनोद देशमुख, पुनीत जैन, हेमराज सिंह, परवेश कुमार गांधी तथा अन्य के पुराने नोटों को अवैध तरीके से बदलने के लिये मेसर्स बीगल मार्केटिंग, मेसर्स सनराइज ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स आरडी ट्रेडर्स, हिमालयन ट्रेडर्स जैसी राजीव सिंह कुशवाहा की मुखौटा कंपनियों का उपयोग किया।

ईडी ने कहा कि मोहित गर्ग, नितिन गुप्ता और कुशवाहा लोगों से चलन से हटाये गये नोट लेते और मुखौटा कंपनियों के खाते में जमा करते। यह काम एक्सिस बैंक के अधिकारियों की मदद से किया गया। उक्त मुखौटा कंपनियों के खातों में जमा राशि को बाद में सोना खरीदने को लेकर अलग-अलग सर्राफा कारोबारियों के खाते में हस्तातंरित कर दिया जाता है।

असंगठित फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को मिलेगी विश्व बैंक की मदद

नई दिल्ली (ए.)। असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को देश एवं दुनिया में मुकाबला करने लायक बनाने के लिए सरकार नया प्रोजेक्ट लांच करने जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रयास से देश के चार राज्यों के 145 जिलों में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पंजाब शामिल हैं। प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए विश्व बैंक मदद करेगा। मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक प्रोजेक्ट के लागू होने से इन चार राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी 90,000 छोटी यूनिट लाभान्वित होंगे। इससे 1.35 लाख रोजगार निकलने का अनुमान लगाया गया है। नई सरकार के गठन के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है। इस प्रोजेक्ट का फायदा छोटे उद्यमियों को मिलेगा। जिनके पास फैक्ट्री लाइसेंस नहीं है और जिन यूनिट में 10 से कम लोग काम कर रहे हो। सरकार की तरफ से किए गए सर्वे में पाया गया था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी 40 फीसदी से अधिक यूनिट के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये यूनिट एफएसएसएआई से भी नहीं जुड़े हुए हैं। सर्वे में यह भी पाया गया है कि इस प्रकार के 70 फीसदी उद्यमियों को अपने काम के विस्तार के लिए फंड जुटाने में भारी दिक्कत होती है। इन उद्यमियों को देश-विदेश में होने वाले बदलाव एवं नए नियमों की कम जानकारी होती है। मंत्रालय के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश के मैन्यूफैक्चरिंग जीडीपी में 14 फीसदी का योगदान देता है, वहीं मैन्यूफैक्चरिंग से निकलने वाले रोजगार में इनकी हिस्सेदारी 13 फीसदी की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का 42 फीसदी उत्पादन गैर संगठित क्षेत्र से आता है।

ताजा खबर
संक्षिप्त

जेट एयरवेज के CFO अमित अग्रवाल ने दिया इस्तीफा

मुंबई (ए.)। वित्तीय समस्याओं के चलते अस्थाई रूप से बंद हुई जेट एयरलाइंस के डेप्युटी चीफ एग्जिक्यूटिव और चीफ फाइनैंशल ऑफिसर अमित अग्रवाल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, 'मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवाओं से त्यागपत्र दे रहा हूं।' बता दें कि अप्रैल से ही जेट एयरवेज का संचालन बंद हो गया है। कई महीनों से पायलट और अन्य कर्मचारियों की सैलरी न दे पाने की वजह से भी एयरलाइन लंबे समय से संकट में घिरी थी। जेट एयरवेज के बंद होने की वजह से हजारों कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी। जेट की हिस्सेदारी खरीदने से भी कंपनियां परहेज कर रही हैं। हालांकि जेट के ही अंतरराष्ट्रीय सहयोगी एतिहाद ने हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है।

ईडी ने चंदा कोचर से की 8 घंटे पूछताछ

आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन कर्ज मामला ।

नई दिल्ली (ए.)। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। ईडी ने दोनों से 8 घंटे तक पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कोचर और उनके पति सोमवार को ईडी के खान मार्केट स्थित दफ्तर पहुंचे। उन्हें 11 बजे ईडी के सामने पेश होना था। हालांकि, दोनों निर्धारित समय से कुछ समय पहले ही पहुंच गए। उन्हें रात 8 बजे वहां से जाने की अनुमति मिली। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि ईडी ने दोनों से किस तरह के सवाल किए। सूत्रों का कहना है कि दोनों को मामले की जांच आगे बढ़ाने में जांच अधिकारी का सहयोग करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि दोनों के बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए। दोनों से मंगलवार को भी पूछताछ होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चंदा कोचर को इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसी के सामने पेश होना था लेकिन कोचर ने समय बढ़ाने की मांग की थी। जिसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई थी।

ईडी ने दीपक कोचर के भाई राजीव कोचर से इस मामले में कई बार पूछताछ की है। सूत्रों ने कहा कि राजीव कोचर सिंगापुर की कंपनी एविस्टा अडवाइजरी के संस्थापक हैं और सीबीआई ने ऋण के पुनर्गठन में उनकी कंपनी की भूमिका के बारे में उनसे पूछताछ की थी। बैंक कर्ज मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक मार्च को छापेमारी के बाद भी चंदा कोचर और उनके पति से ईडी के मुंबई कार्यालय में पूछताछ की थी।

केरल में बिना आधार नहीं मिलेगी सैलरी, सरकार ने लिया यह फैसला

नई दिल्ली (ए.)। आने वाले दिनों में केरल में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। दरअसल, केरल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में आधार अधारित पंचिंग सिस्टम इन्स्टॉल करने का फैसला लिया है। इस पंचिंग सिस्टम में स्पार्क सॉफ्टवेयर के जरिए काम होगा। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी दफ्तरों में अब कर्मचारियों को स्पार्क सॉफ्टवेयर में आधार कार्ड रजिस?टर्ड करने के बाद ही सैलरी मिल सकेगी। सरकारी दफ्तरों के अलावा बायोमेट्रिक पंचिंग सिस्टम को शिक्षा संस्थानों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस नए सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की स्किल और आउटपुट बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस नए सिस्टम के लागू होने से 5 लाख 60 हजार कर्मचारी प्रभावित होंगे। इन कर्मचारियों में राज्य सचिवालय के अधिकारियों से लेकर सरकारी स्कूल के कर्मचारी तक शामिल हैं।

कैसे होगा काम : दरअसल, आधार आधारित बायोमेट्रिक पंचिंग सिस्टम के जरिए फिंगर प्रिंट होती है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की दफ्तर में उपस्थिति दर्ज की जाती है।

10 हजार करोड़ जुटाने की योजना

एयर इंडिया की इकाइयां और संपत्ति बेचेगी सरकार

नई दिल्ली (ए.)। सरकार एयर इंडिया की इकाइयों और दूसरी संपत्तियों को बेचकर 10 हजार करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। सरकार ने एयर इंडिया का 29 हजार करोड़ रुपये का कर्ज अपने ऊपर लिया है। इसे चुकाने के लिए उसने यह योजना बनाई है। एक आला सरकारी अधिकारी ने बताया, 'सरकार को संपत्तियों की बिक्री और विनिवेश से 10 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इस पैसे का इस्तेमाल 29 हजार करोड़ के कर्ज को घटाने के लिए किया जाएगा।' अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी। सरकार ग्राउंड हैंडलिंग, इंजिनियरिंग और रीजनल एयरलाइन सब्सिडरी अलायंस एयर को बेचकर यह पैसा जुटाने की उम्मीद कर रही है। मुंबई में एयर इंडिया की इमारत और दूसरी संपत्तियों को बेचने से कंपनी को 1,400 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पिछले साल सरकार ने एयर इंडिया में 76 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, जो नाकाम रही। उसके बाद केंद्र ने कंपनी की फाइनैंशल रीस्ट्रक्चरिंग की योजना बनाई। कंपनी पर कर्ज का बोझ घटाने के लिए उसने 54 हजार करोड़ के कुल कर्ज में से 29 हजार करोड़ का वर्किंग कैपिटल लोन स्पेशल परपज वीइकल , इंडिया असेट होल्डिंग्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया था। इसके साथ एयर इंडिया की 2,700 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का बोझ सरकार पर आ गया। इससे पहले एयर इंडिया को हर साल 4,400 करोड़ रुपये का ब्याज बैंकों को चुकाना पड़ रहा था। इस बीच, केंद्र ने एयर इंडिया से फाइनैंशल रिजल्ट तैयार करने को भी कहा है। इससे लगता है कि नई सरकार बनने के बाद कंपनी के विनिवेश का काम रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि, अगर एनडीए सरकार की केंद्र में वापसी नहीं हो पाती है तो एयर इंडिया का विनिवेश ठंडे बस्ते में भी डाला जा सकता है। एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खारोला ने इस महीने की शुरुआत में एक मीटिंग बुलाई थी और एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी लोहानी को पत्र लिखकर कंपनी की इकाइयों के विनिवेश की तैयारी करने का निर्देश दिया था। 6 मई 2019 की तारीख वाले इस पत्र में उन्होंने लिखा था, 'मैं आपसे एयर इंडिया और उसकी इकाइयों के वित्त वर्ष 2019 के फाइनैंशल स्टेटमेंट्स तैयार करने की गुजारिश कर रहा हूं। आप इन्हें जून 2019 तक तैयार कर लें।' इकनॉमिक टाइम्स ने भी इस पत्र की एक कॉपी देखी है। इसमें एयर इंडिया से सभी इन्वेंटरी के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी कहा गया है।